ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता में कमी

563. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण, शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में कोई कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक और पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि में कुल कितनी धनराशि के ऋण दिये गये है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री उत्तम भाई एच. पटेल) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण वितरित किए जाते हैं । उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए सभी बैंकों द्वारा ऋणों का समग्र वितरण प्रति वर्ष बढ़ रहा है। सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरण (संलग्न) में यह देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वितरित किया जाने वाला ऋण प्रति वर्ष बढ़ रहा है। तथापि, शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु ऋण वितरण में गिरावट का रुख रहा है। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कोई ऋण घटक नहीं है ।

(ख) शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण वितरण में गिरावट के कारण

(1) शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमेय अधिकतम ऋण 5000/-रुपए था जिसे सबसिडी से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रमों की तुलना में काफी कम समझा गया था। सरकार ने शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम को शहरी सूक्ष्म उद्यमियों की योजना में विलय करने का निर्णय लिया है जहां ऋण की अधिकतम सीमा 16,000 रुपए से 20,000 रुपए तक है। यह विलय अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1.4.1992 से लागू हो जाएगा।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग जिनके लिए 30 प्रतिशत ऋण आरक्षित है, स्वरोजगार की बजाय नौकरी को तरजीह देते हैं ।

(3) कुछ राज्यों में शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 30 प्रतिशत से कम थी।

(ग) सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

वर्ष अवधि (अप्रैल-अक्तूबर)	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण (सभी बैंक)
	(लाख रुपए में)
1988–89	9662.94
1989–90	10499.39
1990–91	10839.97
1991–92	14339.11

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए ऋण

वर्ष	शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु ऋण
	(लाख रूपए में)
1988–89	2082.00
1989–90	1993.47
1990–91	1010.31 (अनन्तिम)
1991–92	उपलब्ध नहीं

Survey of rural water supply

564. KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had launched a nation-wide survey on the status of drinking water supply in rural areas ; if so, by when the data would be ready for utilisation ;

(b) the number of villages fully covered for drinking water supply under the Accelerated Rural Water Supply Programme and the number of villages which still remain uncovered ;

(c) by when these uncovered villages would be benefited by programme ;

(d) whether due to paucity of funds there is slow progress in the implementation of this programme ; if so, whether in order to overcome this difficulty Government are exploring the possibility of setting up a national level financing institution for rural water supply and sanitation projects to attract public contribution and investments in this sector ; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) : (a) Yes, Sir. The results of part I of the survey of status of drinking water supply in rural habitations is likely to be available by end of April, 1992, except for some parts in some States where the survey could not be started on schedule due to climatic or other factors. The results of part II of the survey relating to quality of drinking water are likely to be made available by end of September, 1992.

(b) Out of the identified problem villages numbering 1,61,722 as on 1-4-85, 94871 problem villages have been covered fully, 62186 PVs have been covered partially under the Accelerated Rural Water Supply Programme, Mini-Missions and the Minimum Needs Programme. The remaining 4665 PVs are yet to be provided safe drinking water facilities as per reports received so far from various States/UTs.

(c) All the remaining uncovered problem villages will be provided safe drinking water facilities by 31-3-93.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Shortage of drinking water in Orissa

565. SHRI JAGADISH JANI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that there is an acute problem of drinking water in most of the villages of Orissa ;

(b) if so, the number of problem villages in Orissa ; as on 31st January, 1992 ;